extensive and unscientific workings with difficult geo-mining conditions. Such mines are not readily amenable to large scale mechanisation.

(iii) Most of the ECL mines being located in the State of West Bengal, the consumers taking coal from the ECL mines in West Bengal are required to pay the cesses being levied by the Government of West Bengal. No other State Government is levying any cess on coal.

(iv) ECL has little scope for large scale opencast mining.

(v) The ECL mines are located in thickly populated areas which adversely affect mining operations.

On account of the above reasons, it has not been possible to cover up the accumulated loss of ECL despite the following financial support to ECL provided by the Government of India and CIL:—

(i) Contribution from Coal Price Regulation Account amounting to Rs. 3265 crores.

(ii) Waiver of interest and penal interest amounting to Rs. 1309 crores.

(iii) Conversion of debt into equity in 1997-98 amounting to Rs. 1179 crores.

(iv) A moratorium of three years on repayment and interest payment of non-plan loan of Rs. 259 crores.

(v) Investment by Government of India and Coal India Limited amounting to Rs. 2800 crores at the end of 1997-98.

A fresh package for turn-around of ECL has been proposed which is under the consideration of the Trade Unions. The salient features of the package are:—

(i) One time retirement of employees over 55 years of age through Voluntary Retirement Scheme

(ii) Freezing of wages at the level of 31.12.1998 till the end of the period of National Coal Wage Agreement-VI i.e. 31.6.2001.

(iii) Stoppage of Leave Travel Coricession/Long Leave Travel Concession for a period of two years.

(iv) Single payment for Sunday work with staggered day of rest.

(c) There is no proposal to close down ECL.

(d) Does not arise in view of the answer to part (c) of the question.

Decrease in coal mining in Singrauli Collieries

157. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the mining of coal has been decreased in the Singrauli Collieries;

(b) if so, since when and the reasons therefor;

(c) whether the Singrauli Collieries has decided to further reduce the coal mining;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps taken to remove crisis being faced by Singrauli collieries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) Yes, Sir. There has been a marginal decrease in coal production on NCL operating in Singrauli Coalfields during the period April, 98-January,.99 compared to same period last year.

(b) About 98% of coal production of NCL is linked to power plants and the production and despatch thereof is planned on the basis of projected demand of the linked consumers.

During the year 1998-99, despatches to its linked consumers has suffered because of the following reasons:

(i) For five months from middle of July, 1998, NCL could not supply coal to the Obra Power Station of

UPSEB because of collapse of a railway bridge. While the demand of Obra TPS was met from other sources, despatches from NCL suffered to the extent of 1.5 million tonnes during this period.

(ii) As per the linkages sanctioned, Rihand TPS took 0.88 million tonnes less than their linkages during April ,98 to January, 99.

Keeping in view the above demand constraints and the need to keep the stock at the manageable level, NCL had to cut back production.

(c) and (d) No, Sir.

(e) The above slackness in demand is temporary and the demand from the power houses linked to NCL is expected to increase in the year 1999-2000. Consequently, Coal production will be stepped up.

मधुबन वाशरी परियोजना में आग लगना

158. **श्री शिबू सोरेन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत कोकिंग कोल लि0 की मधुबन वाशरी परियोजना में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरु की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या यह सच हैं कि 12 वर्ष पूर्व दाशरी के निर्माण का ठेका एम0 ए0 एम0 पी0 नामक कंपनी को दिया गया था और इसे तीन वर्षों में पूरा करना था,

(घ) यदि हां, तो इसे आज तक पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं,

(ड़) इस विलंब के कारण हुई आर्थिक क्षति का ब्यौरा क्या हैं, और

(च) सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई कर रही हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां । आग लगने के कारणों की जांच किए जाने के लिए निम्न सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया हैं:-

1.	श्री एस0 पी0 सिंह, निदेशक (तकनीकी) पी0 एण्ड पी0, भा. को. को. लि.	अध्यक्ष
2.	श्री आर. खन्ना, वाशरी प्रमुख, भा0 को0 को लि0	सदस्य
3.	श्री एस. चट्टोपाध्य, सी. जी. एम. (सी. पी./डब्ल्यू. सी./सी.), भाकोकोलि	सदस्य-सचिव
4.	श्री एस. सी. त्रेहन, सी0 जी0 एम0 (एम. एम.), भाकोकोलि	सदस्य
5.	श्री बी. के. भट्टाचार्जी, जी. एम. (वित्त), भोकोकोलि	सदस्य
6.	श्री ए. पी. सिंह क्षेत्रीय निदेशक, आर-1-11, सीएमपीडीआईएल	सदस्य
7.	श्री एस0 घोष, जी0 एम0 (सुरक्षा), भाकोकोलि	सदस्य

(ग) और (घ) मधुबन वाशरी के निर्माण का अनुबंध दिसम्बर, 1985 में मेसर्स माइसिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि. जो भारत सरकार का एक मशीनरी कारपोरेशन लि. जो भारत सरकार का एक उपक्रम हैं, को टर्न-की आधार पर प्रदान किया गया था और एम. ए. एम. सी. द्वारा वाशरी पर प्रदान किया गया था और एम. ए. एम. सी. द्वारा वाशरी को दिसम्बर, 1988 तक पूरा किया जाना था । कंपनी जाना था । कंपनी अभी भी परियोजना लोड आउट व्यवस्था पर कार्य कर रही हैं, यद्यपि उन्होंने मुख्य वाशरी का बड़ा कार्य पूर्ण कर दिया हैं । कंपनी अभी भी परियोजना लोड आउट व्यवस्था पर कार्य कर रही हैं, यद्यपि उन्होंने मुख्य वाशरी का बड़ा कार्य पूर्ण कर दिया हैं । परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण इस प्रकार हैं :-

1. एम. ए. एम. सी. द्वारा देशीय तथा आयातित उपकरणों हेतु आर्डर दिए जाने में हुआ विलंब ।

2. एम. ए. एम. सी. द्वारा जी. ए. ड्राईग के प्रस्तुतिकरण में हुआ विलंब ।

3. एम. ए. एम. सी. द्वारा संयंत्र के निर्माण तथा चालू किए जाने में हुआ विलंब ।

4. वन भूमि की उपलब्धता में हुआ विलंब जिससे क्रास कन्ट्री कन्वेयर्स का कार्य प्रभावित हुआ ।

5. कुछ व्यक्तियों ने अक्तूबर, 85 में बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा भा. को. को. लि. को सौंपी गई भूमि के स्वामित्व का दावा किया था । यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन हैं ।

(ड़) और (च) यह परियोजना फरवरी, 1984 में 71.90 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत की गई थी । इस विलंब के कारण, अक्तूबर, 1993 में स्वीकृत परियोजना की संशोधित लागत अब 194.18 करोड़ रु. हैं । चूंकि एम. ए. एम. सी. वाशरी पर अधिकांश कार्य कर चुकी हैं, अतः अनुबंधकर्ता में परिवर्तन किए जाने से और अधिक विलंब हो सकता था । एम. ए. एम. सी. से बार-बार परियोजना को पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया गया और अन्ततः मधुबंध वाशरी को भा. को. को. लि. द्वारा